

भारत-रूस शिखर सम्मेलन

प्रलिस के लयः

S-400 वायु रक्षा मसल, 'चतुरभुज सुरक्षा संवाद, हदल महासागर क्षेत्र

मेन्स के लयः

भारत-रूस संबंध और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस के राष्ट्रपतल व्लादमलर पुतनल भारत दूरे पर आए । दोनों देशों के मध्य हुए बैठक में कई समझौतों पर हस्ताक्षर कयल गए । यह बैठक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों देशों के वदलश मंत्रयों और रक्षा मंत्रयों के बीच पहली 2+2 (2+2 Meeting) बैठक थी ।

- [अपरैल 2021 भारत और रूस के बीच एक आम सहमतल वकलसतल करने के लयल दोनों देशों के वदलश मंत्रयों](#) ने एक दूसरे की चतलओं से संबंधतल वभलनलन मुद्दों को संबोधतल कयल ।



प्रमुख बदल

- पहली भारत-रूस 2+2 वार्ता: यह दोनों देशों के वदलश और रक्षा मंत्रयों के मध्य पहली 2+2 बैठक है ।
 - 'चतुरभुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड के सदस्य देशों- अमेरकल, जापान और ऑस्ट्रेलयल के साथ 2+2 प्रारूप बैठकों का आयोजतल कयल गया है ।
- कलाशनकलव राइफलस पर समझौता: दोनों पक्षों के मध्य अमेठी, उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त उदयम के तहत लगभग 600,000 एके-203 (AK-203) राइफलस के नरलमाण के लयल दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर कयल गया ।
- सैन्य सहयोग के लयल समझौता: दोनों देशों द्वाारा अगले दशक वर्ष 2021 से 2031 तक के एक सैन्य प्रौद्योगकल सहयोग के लयल एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कयल गया ।
 - भारत ने सरलफ एक खरीदार के रूप में रूस का रक्षा वकलस और उत्पादन भागीदार बनने के अपने लक्ष्य को रेखांकतल कयल ।

- दोनों पक्ष अब सैन्यअभ्यासों के प्रारूप का वसितार करने पर वचिार कर रहे हैं ताकि उन्हें और अधिक प्रगाढ़ किया जा सके और साथ ही मध्य एशिया में भारत-रूस सहयोग के वसितार पर भी वचिार किया जा सकें।
- **रसद समझौते के पारस्परिक आदान-प्रदान को आगे बढ़ाना:** रक्षा बकिरी से परे, रसद समझौते का पारस्परिक आदान-प्रदान **Reciprocal Exchange of Logistics Agreement- RELOS** नौसेना से सैन्य सहयोग समझौता ज्जापन नषिकर्ष के उन्नत चरणों में है।
- **सैन्य प्रोटोकॉल:** दोनों देशों द्वारा सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग ((IRIGC-M&MTC) पर 20वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया।
 - 'IRIGC-M&MTC' पछिले दो दशकों से एक अचछी तरह से स्थापित तंत्र है, जो रक्षा सहयोग के लिये पारस्परिक रूप से सहमत एजेंडे पर चर्चा करने और लागू करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- **एस-400 एयर डफिंस ससिस्टम डील:** भारत ने ज़ोर देकर कहा कि वह एक "स्वतंत्र वदिश नीति" का पालन करता है, जो **अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रु सेंकशंस एक्ट (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA)** की ओर इशारा करता है।
 - इसे **S-400 वायु रक्षा मसिाइल (S-400 Air Defence Missile)** प्रणालियों की आपूर्ति के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है।
- **भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट पर चर्चा:** अफगानसिस्तान, मध्य पूरव की स्थिति के साथ मध्य एशिया का व्यापक प्रभाव है।
 - समुद्री सुरक्षा और इसकी हफिजाजत पर दोनों देशों द्वारा साझा चिंता व्यक्त की गई।
 - बैठक में चीन के आक्रामक रुख का मुद्दा भी उठाया गया।
 - दोनों देशों द्वारा मध्य एशिया और **हदि महासागर क्षेत्र** में अधिक से अधिक जुड़ाव का प्रस्ताव रखा गया।

भारत के लिये रूस का महत्त्व

- **चीन को संतुलित करना:** पूरवी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रमण ने भारत-चीन संबंधों को एक मोड़ पर ला दिया, लेकिन यह भी प्रदर्शित किया कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान देने में सक्षम है।
 - लद्दाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस ने भारत और चीन के वदिश मंत्रियों के बीच एक त्रपिक्षीय बैठक आयोजित की।
- **आर्थिक जुड़ाव के उभरते नए क्षेत्र:** हथियारों, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा और हीरे जैसे सहयोग के पारस्परिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों के उभरने की संभावना है। इनमें खनन, कृषि-औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी, जसिमें रोबोटिक्स, नैनोटेक तथा बायोटेक शामिल हैं।
 - रूस के सुदूर पूरव और आर्कटिक में भारत के पदचिन्हों का वसितार होना तय है। कनेक्टविटी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मलि सकता है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** भारत और रूस अफगानसिस्तान के बीच की खाई को पाटने के लिये काम कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान कर रहे हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों का समर्थन:** इसके अतिरिक्त रूस एक सुधारित **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।
- **रूस का सैन्य नरियात:** रूस भारत के लिये सबसे बड़े हथियार नरियातकों में से एक रहा है। यहाँ तक कि वर्ष 2011 से 2015 की तुलना में पछिले पाँच वर्ष की अवधि में भारत को हथियारों के आयात में रूस की हसिसेदारी 50% से अधिक गरि गई।
 - वैश्विक हथियारों के व्यापार की नगिरानी करने वाले 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रसिर्च इंस्टीट्यूट' के अनुसार, पछिले 20 वर्षों में भारत ने रूस से 35 बलियिन अमेरिकी डॉलर के हथियार और सैन्य सामग्री आयात की है।

आगे की राह

- **समय पर रख-रखाव सहायता प्रदान करने के लिये रूस:** भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिये पुर्जों की समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत के संदर्भ में एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
 - इसे संबोधित करने के लिये रूस ने वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते के बाद अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देते हुए वधायी परिवर्तन किये हैं।
 - इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करने की ज़रूरत है।
- **एक दूसरे के महत्त्व को स्वीकार करना:** रूस आने वाले दशकों तक भारत के लिये एक प्रमुख रक्षा भागीदार बना रहेगा।
 - दूसरी ओर रूस और चीन वर्तमान में एक अर्द्ध-गठबंधन एलायंस में हैं। रूस बार-बार दोहराता है कि वह खुद को किसी के कनषिट भागीदार के रूप में नहीं देखता है। इसलिये रूस चाहता है कि भारत उसके लिये एक संतुलक का काम करे।
- **संयुक्त सैन्य उत्पादन:** दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देशों को रूसी मूल के उपकरण और सेवाओं के नरियात के लिये भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं।

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस